



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 27 मार्च, 2024

चैत्र 7, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-9

संख्या 586/नौ-9-2024-45 ज-17 टी0सी0

लखनऊ, 27 मार्च, 2024

अधिसूचना

प0आ0-90

भारत के 13वें वित्त आयोग द्वारा दी गयी संस्तुतियों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड की स्थापना और उसके निगमन की व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश की अधिसूचना सं०-346/79-वि०-1-11-1 (क)/14-2011 दिनांक 18 मार्च, 2011 द्वारा उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 बनाया गया और उसकी धारा-4 की उपधारा (1) के अधीन तदनुसार अधिसूचना सं०-649/नौ-9-2011, दिनांक 30 मार्च 2011 जारी की गयी। अधिसूचना सं०-983/नौ-9-2016-80ज-2011, दिनांक 17 अगस्त, 2016 द्वारा अधिनियम की धारा-36 के अधीन उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड (प्रक्रिया का विनियमन एवं इसके कृत्यों का निष्पादन) नियमावली, 2016 बनायी गयी।

2-उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम 2011 की धारा 10 के खण्ड (झ) और उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड (प्रक्रिया विनियमन एवं इसके कृत्यों का निष्पादन) नियमावली, 2016 के नियम 19 में उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड की वार्षिक कार्य-योजना तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत करने और सरकारी गजट में प्रकाशित करने के प्राविधानों के अधीन बोर्ड की वर्ष 2023-24 की कार्य योजना निम्नवत् है:-

(1) प्रदेश की विह्वलित नगर पंचायतों नगर पालिका परिषदों और नगर निगमों की वित्तीय क्षमता की समीक्षा करने और राजस्व के विभिन्न संसाधनों की कार्य क्षमता के निर्धारण की दृष्टि से विगत 03 वर्षों में आकलनगत नगरीय निकायों की कर एवं करेतर मदों में प्राप्त उपलब्धियों और नगरीय निकायों द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों की तुलनात्मक समीक्षा के साथ उनका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। इसके अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों, क्षमता और सम्भावनाओं के सापेक्ष उन नगरीय निकायों की वित्तीय उपलब्धियों में कितना अन्तर विद्यमान है और इस अन्तर को कम/समाप्त करने की दिशा में

निकायों द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही और प्रयासों का भी अध्ययन किया जाएगा। आंकलनगत इन नगरीय निकायों में 05 नगर निगम, 20 नगर पालिका परिषदों और 50 नगर पंचायतें होंगी जिनका चयन उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड द्वारा किया जाएगा। अध्ययनोपरान्त समीक्षात्मक टिप्पणी सम्बन्धित निकायों, स्थानीय निकाय निदेशालय और नगर विकास विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी जिसके आधार पर सम्बन्धित नगरीय निकायों के वित्तीय संसाधनों, कराच्छादन की स्थिति, कर एवं करेतर देयों की वसूली आदि का नियमित अनुश्रवण किया जाएगा।

(2) प्रदेश की समस्त नगरीय स्थानीय निकायों में कर एवं करेतर देयों की मदवार माँग और उनके सापेक्ष की गई वसूली की गत तीन वर्षों के आँकड़े प्राप्त कर उनकी समीक्षा की जाएगी और औसत से कम वसूली करने वाली निकायों के स्पष्टीकरण प्राप्त कर अभिमत सहित संस्तुति शासन को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) राज्य में नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों की स्वामित्व वाली सम्पत्तियों, प्रबन्धनगत सम्पत्तियों और निहित सम्पत्तियों को सम्बन्धित नगरीय निकायों द्वारा चिह्नांकित और प्रगणित कराकर डिजिटलाइज कराने और डाटा बेस तैयार कराने के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। जिन निकायों से एतदसम्बन्धी विवरण अप्राप्त है, उनसे निर्धारित प्रारूप पर उक्त विवरण प्राप्त किये जाएँगे और अपूर्ण प्राप्त विवरणों को पूर्ण किया जाएगा। इस आधार पर साफ्टवेयर में तदनुसार प्रविष्टियाँ कर इस संबंध में डाटाबेस तैयार करने की कार्यवाही की जाएगी।

(4) नगरीय निकायों में सम्पत्ति कर (सामान्य कर जल कर जल निकास कर) एवं अन्य राजस्व संसाधन प्रणाली की समीक्षा करने और कराच्छादन की दृष्टि से सम्पत्तियों का चिन्हांकन, मूल्यांकन, कर निर्धारण, केन्द्र सरकार के भवनों पर सेवा प्रभार की देयता एवं करेतर मदों और कर की दरों हेतु उपयुक्त आधार से अवगत कराने की दृष्टि से नगरीय निकायों के अधिकारियों, विशेषकर राजस्व से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को संवेदनशील और जवाबदेह बनाने के लिए उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम 25 जनपदों में कार्यशालायें और बैठकें आयोजित की जाएगी। इन कार्यशालाओं और बैठकों में निकाय क्षेत्र में अवस्थित विभिन्न श्रेणी की शत प्रतिशत सम्पत्तियों को कराच्छादित करने की दृष्टि से भौगोलिक सूचना प्रणाली के समुचित उपयोग से सम्पत्तियों के चिन्हांकन, वार्षिक मूल्य की गणना की पारदर्शी प्रक्रिया के अन्तर्गत मासिक किराया दर के निर्धारण, स्व कर निर्धारण प्रणाली को लोकप्रिय बनाने, प्रयोक्ता प्रभार, अनुज्ञप्ति शुल्क एवं अन्य करेतर संसाधनों के वृद्धि एवं विकास के लिए उपविधियों के गठन और दयों की प्रभावी वसूली के संबंध में जानकारी देने, तद्विषयक विचार विनिमय करने और एतदसम्बन्धी जिज्ञासाओं और शंकाओं का समाधान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

(5) कराधिरोपण के दृष्टिगत वार्षिक मूल्य की गणना हेतु सम्पत्तियों के मूल्यांकन और उनके सत्यापन के लिए निरीक्षण की पारदर्शी प्रक्रिया, अभिकल्पित और निरूपित करने के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यशालाओं और बैठकों में पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

(6) उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में कतिपय प्रकार की सम्पत्तियों को सामान्य कर (गृह कर) के अधिरोपण से मुक्त रखा गया है तो कुछ प्रकार की सम्पत्तियों पर जल कर लगाने पर प्रतिबन्ध है। केन्द्रीय सरकार के भवनों पर कर न लगाने का प्रावधान है जबकि इन पर सेवा प्रभार लिए जाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार नगरीय निकायों द्वारा अपनी सम्पत्तियों का मूल्यांकन नहीं किया जाता। इन सभी प्रकार की सम्पत्तियों का मूल्यांकन अपेक्षित है। जिस सम्पत्ति पर जिस प्रकार के कर की देनदारी से छूट है, उन्हें तदनुसार उस कर की छूट दे दी जाएगी और उन पर जो अन्य प्रकार के कर देय है, बिना वार्षिक मूल्यांकन के गणना किए सम्भव न हो सकेगा। अतः यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र में अवस्थित सभी प्रकार की सम्पत्तियों का वार्षिक मूल्यांकन कर उसे निर्धारण सूची में अंकित किया जाय और तदुपरान्त देय कर से यथाप्रावधान छूट प्रदान की जाय।

(7) सम्पत्ति कर के नियतकालिक पुनरीक्षण के लिए अधिनियम में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत मासिक किराया दर का निर्धारण और सम्पत्तियों का चिन्हांकन के उपयुक्त तौर-तरीके प्रयोक्ता प्रभारों शुल्कों का अधिरोपण, देयों की संग्रह प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से संस्तुतियाँ देने के दृष्टिकोण से देश के विभिन्न राज्यों का भ्रमण कर वहाँ की नगरीय निकायों का अध्ययन किया जाएगा और तदनुसार संस्तुतियाँ प्रस्तुत की जाएँगी। यह कार्यवाही बोर्ड में स्थायी रूप से अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के उपरान्त की जा सकेगी।

(8) नव गठित नगर पंचायतों में पदस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों को निकायों में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों राजस्व स्रोतों, निकाय में निहित सम्पत्तियों के रख-रखाव, कराच्छादन की प्रक्रिया और प्रयोक्ता प्रभारों और अन्य करेतर देयों के अधिरोपण, अभिलेखीकरण और ऑकड़ों का कम्प्यूटरीकरण आदि के संबंध में विशेष रूप से प्रशिक्षित और जागरूक करने की कार्यवाही की जाएगी।

(9) नगरीय निकायों में सम्पत्ति कर विवादों को न्याय निर्णीत करने की प्रक्रिया और विनियमन हेतु उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड विनियम का आलेख्य राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित होने पर तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(10) राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा करने अथवा संकल्प के माध्यम से नगरीय स्थानीय निकायों का अनुरोध प्राप्त होने पर कर और करेतर मदों सहित विभिन्न वित्तीय संसाधनों, कराधिरोपण हेतु सम्पत्तियों के चिन्हांकन, मूल्यांकन, कर निर्धारण, मासिक किराया दर का निर्धारण, अधिनियम और नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अपेक्षित कार्यवाही, स्व कर निर्धारण प्रणाली के क्रियान्वयन उपविधियों के गठन आदि विभिन्न विषयों परामर्श और अभिमत उपलब्ध कराया जाएगा।

(11) नगरीय स्थानीय निकायों में वित्तीय प्रबन्धन, लेखा प्रणाली के सुदृढीकरण और वित्तीय क्षमता संवर्धन के उपायों, लेखाभिलेखों के समुचित रख रखाव और दोहरी लेखा प्रणाली के अध्ययन के लिए विशेषज्ञों/विशेषज्ञ संस्थाओं की सेवाएँ प्राप्त की जायेगी और उनके द्वारा संस्तुत सुधारों के संबंध में संस्तुति शासन को प्रस्तुत की जाएगी।

(12) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचना में विनिर्दिष्ट नगरीय स्थानीय निकायों में भवन भूमि या दोनों के कर निर्धारण हेतु उनका चिन्हांकन, मूल्यांकन और वार्षिक मूल्य की गणना सुनिश्चित की जाएगी।

(13) नगरीय स्थानीय निकायों में वित्तीय संसाधनों कर एवं करेतर मदों, सम्पत्ति कर अधिरोपण प्रक्रिया, वसूली, अभिलेखीकरण, कम्प्यूटराइजेशन और एतद्सम्बन्धी अन्य सुसंगत विषयों पर सम्बन्धित अधिकारियों को समय-समय पर नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के साथ संयुक्त रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा और विभिन्न कालावधि के प्रशिक्षण के लिए तैयार किए गए माड्यूल के आधार पर यथावश्यकता अध्ययन सामग्री और पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन तैयार कराए जाएँगे।

(14) अन्य ऐसे कृत्यों का निष्पादन किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 अथवा तदधीन बनाई गई नियमावली में प्रावधानित हैं अथवा ऐसे संगत विषयों और बिन्दुओं पर परामर्श, अभिमत, टिप्पणी या परामर्श प्रस्तुत किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अपेक्षा की जाय अथवा प्रदेश के किसी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा संकल्प के माध्यम से अनुरोध किया जाय।

(15) ऐसे विषयों या कृत्यों को निष्पादित किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के गठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझा जाय या उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 या तदधीन बनाई गई उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड (प्रक्रिया का विनियम एवं इसके कृत्यों का निष्पादन) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अधीन हो।

आज्ञा से,
अरुण प्रकाश,
विशेष सचिव।